राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16830/2022

मीनाक्षी त्रिवेदी पुत्री श्री केशव कांत त्रिवेदी पत्नी श्री अनीश पालीवाल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी 17-बी रातखेत सामने रॉयल गार्डन उदयपुर वर्तमान में 7-सी, वर्धमान नगर, उत्तरी सुंदरवास, सामने वर्धमान स्कूल, उदयपुर, राजस्थान।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. आयुक्त, कृषि विभाग आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।

4. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), आयुक्तालय पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।

5. अधीक्षण अभियंता, पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटर शेड सेल कम डेटा सेंटर, प्रतापगढ़, उदयपुर।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री पृथ्वी राज सिंह जोधा।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री महेश चंद्र बिश्नोई।

माननीय जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

रिपोर्ट करने योग्य निर्णय

16/01/2024 को आरक्षित

25/01/2024 को उद्घोषित

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका को निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए प्राथमिकता दी गई हैः "इसलिए, यह विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को कृपया अनुमति दी जाए और एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश द्वारा, 31.03.2022 (अनुलग्नक-5) दिनांकित संचार को कृपया रद्द और अलग किया जाए। यह कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित नियम, 1996 को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को किसी भी उपयुक्त पद पर नियुक्ति का हकदार ठहराया जा सकता है। यह कि प्रत्यर्थियों को मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित नियम, 1996 को देखते हुए याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार किसी भी उपयुक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया जा सकता है। कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित याचिका को कृपया लागत के साथ अनुमति दी जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता श्री केशव कांत त्रिवेदी (दिवंगत सरकारी कर्मचारी) की विवाहित बेटी है। श्री केशव कांत त्रिवेदी का कोविड-19 के कारण 20.01.2021 को निधन हो गया, जब वे वाटर शेड सेल सह डेटा सेंटर, प्रताप नगर, उदयपुर (प्रतिवादी विभाग) के कार्यालय में कार्यकारी अभियंता के पद पर सेवा में थे।

2.1. याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 अधीक्षक अभियंता के समक्ष राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 (इसके बाद '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद प्रतिवादी

संख्या 5 ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी को दिनांक 02.03.2021 के संचार के माध्यम से उक्त आवेदन को अग्रेषित किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 5 ने मामले को फिर से प्रत्यर्थी संख्या 3 को भेजा, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

2.2 इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 4-अतिरिक्त निदेशक ने प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांकित 31.03.2022 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से सूचित किया कि वर्तमान मामले में, 1996 के नियमों के नियम 2 के तहत निहित 'आश्रित' की परिभाषा के अनुसार, जैसा कि 2021 में आगे संशोधन किया गया है, मृतक सरकारी कर्मचारी का एक बेटा था- पुनीत त्रिवेदी, और इसलिए, उस हिसाब से, याचिकाकर्ता को मृतक सरकारी कर्मचारी का आश्रित नहीं माना जा सकता है।2.3 याचिकाकर्ता ने 10.10.2022 दिनांकित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और 01.11.2022 दिनांकित एक नोटिस भी दिया, लेकिन उत्तरदाताओं ने उस संबंध में कुछ नहीं किया। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2022 के विवादित संचार/पत्र से व्यथित होने के कारण, पूर्व-उद्धृत राहतों का दावा करने वाली वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1996 के नियमों के संशोधन से पहले विवाहित बेटी को 'आश्रित' की परिभाषा से बाहर करना भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन है। इस तरह की दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (सिविल संदर्भ संख्या 1/2022, और 13.09.2022 को तय किए गए अन्य संबंधित मामलों) के मामले में इस माननीय न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

3.1. विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी की विवाहित बेटी है और उसने निर्धारित समय सीमा के

भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन प्रत्यर्थियों ने इस तरह की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को केवल इस कारण से खारिज कर दिया कि मृतक सरकारी कर्मचारी का बेटा-पुनीत त्रिवेदी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है, जो उचित नहीं है, क्योंकि विवाहित बेटी 'प्रियंका श्रीमाली (उपरोक्त)' के मामले में माननीय वृहद पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार विचाराधीन नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है।

3.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र (आर. एस.-सी. आई. टी.) के प्रमाण पत्र के साथ एक अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड है और वह विचाराधीन नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मृतक सरकारी कर्मचारी का बेटा पुनीत त्रिवेदी (याचिकाकर्ता का भाई) संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है, सभी संभावनाओं में, भारत में स्थायी रूप से नहीं रहेगा, और माँ (मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी) सहित परिवार की जिम्मेदारियों को भी वहन नहीं करेगा, और इसलिए, याचिकाकर्ता 1996 के नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने के उद्देश्य से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एकमात्र आश्रित सदस्य है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि संशोधन को 1996 के नियमों के तहत राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा दिनांकित 28.10.2021 अधिसूचना के माध्यम से शामिल किया गया था, जिसके तहत, विवाहित बेटी को आश्रितों की श्रेणी में जोड़ा गया था, लेकिन यह वर्तमान मामले में लागू नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता (मृत सरकारी कर्मचारी) की अवधि 20.01.2021 पर समाप्त हो गई थी और उक्त संशोधन को

पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है; इसे केवल संभावित रूप से लागू किया जाना है क्योंकि इसे उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 07.01.2022 की संसूचना में कहा गया था।

4.1. विद्वान वकील ने आगे कहा कि भले ही उपरोक्त संशोधित नियम लागू किए गए हों, श्रीमती लीला त्रिवेदी (मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी) और बेटा पुनीत त्रिवेदी आश्रितों की पहली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और यदि पहली श्रेणी के आश्रित उपलब्ध नहीं हैं, तो विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है, और इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को उत्तरदाताओं द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

4.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अनुकंपा नियुक्ति केवल राज्य सरकार की नीति में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की पूर्ति पर दी जा सकती है, और इसलिए नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की पहली श्रेणी में नहीं आता है, इस प्रकार, विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए पात्र नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णय के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय केशव कांत त्रिवेदी (सरकारी कर्मचारी) की विवाहित बेटी है, जिसकी मृत्यु 20.01.2021 पर हुई थी, जब वह प्रतिवादी विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर सेवा कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष 1996 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांकित 02.03.2021 संचार के माध्यम से भेजा गया था।

6.1. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने प्रत्यर्थी संख्या 5 को

दिनांक 31.03.2022 के विवादित पत्र के माध्यम से सूचित किया जिसमें कहा गया है कि 1996 के नियमों के नियम 2 के तहत निहित 'आश्रितों' की परिभाषा के अनुसार, जैसा कि वर्ष 2021 में और संशोधित किया गया है, वर्तमान मामले में मृतक सरकारी कर्मचारी का एक बेटा पुनीत त्रिवेदी है, और इसलिए, याचिकाकर्ता (विवाहित बेटी) को ऐसी परिस्थितियों में मृतक सरकारी कर्मचारी का आश्रित नहीं माना जा सकता है।

6.2. इस न्यायालय ने आगे कहा कि 1996 के अधिनियम के नियम 2 (सी) को राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा दिनांकित अधिसूचना 28.10.2021 के माध्यम से संशोधित किया गया था; संशोधित नियम 2 (सी) को इसके तहत पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -"2(ग) "आश्रित" का अर्थ है-

(i) पति या पत्नी, या (ii) मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे सहित, या (iii) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी, जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद ली गई बेटी भी शामिल है, या (iv) विवाहित बेटी, यदि खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं है, या (v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में मां, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन, जो अपनी मृत्यु के समय पूरी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थी।"

6.3. यह न्यायालय यह भी देखता है कि दिनांक 28.10.2021 की अधिसूचना जारी करने से पहले, विवाहित बेटी को 1996 के अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत आश्रितों की परिभाषा के तहत तब तक शामिल नहीं किया गया था जब तक कि प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के मामले में बड़ी पीठ द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया था।

संशोधन से पहले नियम 2 (सी) में निहित आश्रित की परिभाषा को इस प्रकार दोहराया गया हैः-"2 (सी)" आश्रित "का अर्थ है पति या पत्नी, बेटा, अविवाहित या विधवा बेटी, गोद लिया हुआ बेटा/गोद ली हुई अविवाहित बेटी" जिसे मृतक सरकारी कर्मचारी ने अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिया था और जो अपनी मृत्यु के समय पूरी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे। यह न्यायालय आगे बताता है कि 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत आश्रित की परिभाषा में 'विवाहित बेटी' शब्द दिनांकित 28.10.2021 संशोधन अधिसूचना से पहले नहीं थे। इस मोड़ पर, प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना उचित माना जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः - "शुरू में, यह देखा जा सकता है कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को संकट से उबरने में मदद करना है, जिसका दुर्भाग्य से वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण सामना कर रहे हैं। इरादा यह सुनिश्चित करना है कि परिवार आपदा का सामना करने में सक्षम हो और इसलिए, आश्रितों को तत्काल नियुक्ति के अनुसार हमेशा जोर दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में, हालांकि 1996 के नियमों के प्रावधान यानी नियम 2 (सी) जो आश्रित को परिभाषित करता है, में पहले से ही 28.10.2021 को संशोधन किया गया है। जिसमें विवाहित बेटी को भी परिभाषा में शामिल किया गया है, कुछ शर्तों के अधीन, हालांकि सभी वर्तमान मामलों में सरकारी कर्मचारियों/कर्मचारियों की प्रावधान में संशोधन की तारीख से पहले मृत्यु हो गई है, आवेदक-याचिकाकर्ताओं के मामले असंशोधित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और असंशोधित प्रावधान के तहत, आश्रित की परिभाषा में 'अविवाहित' बेटी की शर्त के कारण, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई

चुनौती को केवल इस तथ्य के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रावधान में 28.10.2021 से संशोधन किया गया है।

.....

उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह देखा जा सकता है कि व्यावहारिक रूप से सभी उच्च न्यायालय, आश्रित/परिवार की परिभाषा से एक विवाहित बेटी के बहिष्कार की वैधता का परीक्षण करने के बाद सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त बहिष्कार असंवैधानिक था। इसके अलावा, अब माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के रखरखाव और कल्याण के तहत, माता-पिता की देखभाल और रखरखाव के लिए बेटे और बेटी दोनों पर समान कर्तव्य रखा गया है और इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति देने के उद्देश्य से एक विवाहित बेटे को एक विवाहित बेटी से अलग करने की कथित धारणा को कायम नहीं रखा जा सकता है। नियमों के संदर्भ में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बढ़ाने के लिए यार्डस्टिक मृतक सरकारी कर्मचारी पर आश्रितों की निर्भरता है और होनी चाहिए और इसलिए, उनकी वैवाहिक स्थिति केवल अनुकंपा के आधार पर विचार के लिए एक बाधा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, यहाँ पहले उद्धृत परिभाषा की आवश्यकता यहाँ तक कि पति/पत्नी, बेटे और अविवाहित बेटियों के लिए भी आवश्यक है कि वे अपनी मृत्यु के समय पूरी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हों और इसलिए, परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल करने से नियम की उक्त आवश्यकता कम नहीं होगी। इसके अलावा, विवाह अपने आप में अयोग्यता नहीं हो सकती है और इसलिए, एक विवाहित बेटी को केवल उसकी शादी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से रोकने वाली परिभाषा स्पष्ट रूप से मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 (2) का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, परिभाषा से 'अविवाहित' शब्द को रद्द करने के बाद भी, यह केवल लंबित मामलों पर ही लागू होगा

क्योंकि संभावित आवेदक, जिनके खिलाफ कार्रवाई का कारण बहुत पहले ही सामने आ गया था, वे अनुकंपा नियुक्तियों के अनुदान के उद्देश्य के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार की गई घोषणाओं को देखते हुए पात्र नहीं होंगे। सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से। जिन मामलों में सरकारी कर्मचारी की बहुत पहले मृत्यु हो गई है, परिभाषा से शब्द को हटाना, अपने आप में किसी भी आवेदक को कार्रवाई का कोई नया कारण प्रदान नहीं करेगा और इसलिए, व्यक्त की गई आशंका का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त चर्चा से, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) में 'अविवाहित' शब्द का उपयोग एक विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार के अधिकार से वंचित करता है, समानता खंड का उल्लंघन करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, संदर्भ का निपटारा कर दिया जाता है। संदर्भ में पुनर्निर्धारित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः-1996 के नियमों के नियम 2 (सी) का प्रावधान, जो विवाहित बेटी को इसके संशोधन से पहले आश्रित की परिभाषा से बाहर करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघन है और इस तरह, 'आश्रित' की परिभाषा से 'अविवाहित' शब्द को हटा दिया गया है। इसके अलावा, 1996 के नियमों के नियम 5 में भी अविवाहित बेटी/गोद ली हुई अविवाहित बेटी शब्द को बेटी/गोद ली हुई बेटी के रूप में पढ़ा जाएगा। नतीजतन, यह निर्देश दिया जाता है कि परिभाषा से 'अविवाहित' शब्द को हटाने के कारण-(i) यह किसी भी मामले को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें इस आदेश से पहले के प्रावधानों के तहत अनुकंपा नियुक्ति पहले ही दी जा चुकी है; (ii) यह अपने आप में किसी भी आवेदक को कार्रवाई का कारण प्रदान नहीं करेगा और उन मामलों पर लागू होगा

जो या तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और/या उन मामलों पर जहां मुकदमेबाजी केवल इस आदेश की तारीख को लंबित है; (iii) आवेदक के मृत्यु के समय मृत सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर होने के संबंध में परिभाषा के प्रावधान और अन्य आवश्यकताओं को ईमानदारी से लागू किया जाएगा; (iv) अनुकंपा नियुक्ति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का भी सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। (v) 'आश्रित' की परिभाषा में 'विवाहित बेटी' को शामिल करने के अलावा नियमों के अन्य सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे।

7. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता के पिता (मृत सरकारी कर्मचारी) की मृत्यु 20.01.2021 को हो गई थी और वही अनुलग्नक-1 में परिलक्षित हुआ था, जिसके बाद, याचिकाकर्ता ने तुरंत प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया; इसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांकित 02.03.2021 संचार के माध्यम से भेजा गया था।

7.1. इस न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत आश्रित की परिभाषा में संशोधन किया और उक्त संशोधन की प्रयोज्यता प्रकृति में संभावित थी, न कि पूर्वव्यापी, और यही उत्तरदाता दस्तावेज़ (जवाब का अनुलग्नक आर/1) द्वारा कहा गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला 'आश्रित' की संशोधित परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से पेश किया गया है।

8. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता का मामला 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा के अनुसार शासित होता है, और उक्त पुरानी परिभाषा में, विवाहित बेटी को प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के मामले में बड़ी पीठ द्वारा

शामिल किया गया था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि केवल नियम 2 (सी) के तहत वर्तमान परिभाषा में "विवाहित बेटी" शब्द को स्थान मिलता है, यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं है; लेकिन उक्त शर्त का उल्लेख 1996 के नियमों में निहित 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा में नहीं किया गया है।

9. इस न्यायालय ने आगे कहा कि 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में पहली श्रेणी के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है, और विवाहित बेटी को भी प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के उपरोक्त पूर्ववर्ती कानून में बड़ी पीठ द्वारा शामिल किया गया था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी की बेटी है और मृतक सरकारी कर्मचारी का भी एक बेटा था-पुनीत त्रिवेदी, और 1996 के नियमों के नियम 2 (सी) के तहत 'आश्रित' की वर्तमान परिभाषा के अनुसार, जैसा कि 28.10.2021 को अधिसूचित किया गया है, बेटा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की पहली श्रेणी में आता है; लेकिन वर्तमान मामला 'आश्रित' की वर्तमान परिभाषा के तहत शासित नहीं है, बल्कि यह पुरानी परिभाषा द्वारा शासित है, क्योंकि मामला और कार्रवाई का कारण और साथ ही प्रश्न में अधिकांश अभ्यास दिनांकित 28.10.2021 संशोधन अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित है।

10. यह न्यायालय यह भी देखता है कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई, और उसके बाद, पूरे परिवार को न केवल भावनात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि वित्तीय कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरा परिवार उस पर निर्भर था, और इसलिए अनुकंपा नियुक्ति शोक संतप्त परिवार को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, एक विवाहित बेटी, मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में, कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार भी, विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है।

11. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ पूर्व-उद्धृत पूर्ववर्ती कानून को देखते हुए, वर्तमान याचिका को अनुमति दी। तदनुसार, दिनांक 31.03.2022 (अनुलग्नक-5) के आक्षेपित संचार को रद्द करते हुए और अलग करते हुए, उत्तरदाताओं को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को इस तरह की अनुकंपापूर्ण नियुक्ति के सभी लाभ संभावित रूप से काम करेंगे। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।